

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-50/1997

- 1-सुरेशकुमार पुत्र ताराचन्द
- 2-राजकुमार उर्फ रामकुमार पुत्र ताराचन्द
- 3- कमला बेवा ताराचन्द
- 4-मु० कृष्णा पुत्री ताराचन्द स्त्री मनोजकुमार जाति जांगिड निवासी ओजटूर तहसील चिडावा जिला झुन्डुन ।
- 5- मु० दर्शना पुत्री ताराचन्द
- 6- महावीर प्रसाद पुत्र झुथाराम
- 7- सुमेर पुत्र झुथाराम
- 8- रणावीरसिंह उर्फ लीलाधर पुत्र झुथाराम
- 9- "सूतक" रामजीलाल पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी चनाना तहसील चिडावा जिला झुन्डुन"-दौराने अपील दि० 28-8-99 को देहान्त हो गया ।"
- 9/1-मोहरी बेवा
- 9/2-शाशाराम पुत्र
- 9/3-महेन्द्र पुत्र
- 9/4-ओमप्रकाश पुत्र
- 9/5-मु० परमेश्वरी पुत्री रामजीलाल स्त्री मातुराम जाति जाट निवासी जोधा का बास तहसील चिडावा जिला झुन्डुन।
- 9/6-मु० अणाची पुत्री रामजीलाल स्त्री सुमेरसिंह जाति जाट निवासी जोधा का बास तहसील चिडावा जिला झुन्डुन ।
- 9/7- बिमला पुत्री रामजीलाल स्त्री चन्द्रभान जाति जाट निवासी ढाढोतकंला
- 9/8-निम्बों पुत्री रामजीलाल स्त्री ओमप्रकाश तहसील चिडावा जिला झुन्डुन

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

- 1- सुलतान
- 2- रामनिवास

3- "सूतक" मु० गिनोडी बेवा हनुमान जाति जांगिड निवासी खातीयों की दाणी लोटिया व निवासी चनाना तहसील चिडावा जिला झुन्डुन" नोट दौराने

- 3/1- मणीदेवी पुत्री स्व० झथाराम स्त्री होशियारसिंह जाति जांगिड निवासी हुस्मा की टाणी तहसील खेतडी जिला झुन्झुन ।
- 4- घनश्याम पुत्र हरचन्द जाति महाजन निवासी चनाना तहसील चिडावा जिला झुन्झुन ।
- 5- मृतक" झण्डूराम पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी पुरानी बस्ती चनाना तहसील चिडावा जिला झुन्झुन" नोट दौराने अपील दिनांक 26-6-2002 को देहान्त हो गया।"
- 5/1- सोनीदेवी बेवा
- 5/2- रोहिताशकुमार पुत्र
- 5/3- धर्मवीर पुत्र
- 6- शेरसिंह उर्फ अशोक पुत्र ताराचन्द
- 7- विनोद उर्फ अश्वती पुत्र बाबुलाल
- जाति जाट निवासी पुरानी बस्ती चनाना तहसील चिडावा जिला झुन्झुन ।
- जाति जांगिड निवासी चनाना तहसील चिडावा जिला झुन्झुन नाबालिगान जरिये वली अदालती श्री नरेशकुमार एडवोकेट झुन्झुन तहसील व जिला झुन्झुन ।

---रेस्पोंडेन्ट---

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक
10-10-1997 द्वारा उप खण्ड
अधिकारी झुन्झुन ।

उपस्थिति-

- 1- श्री जगदीशचन्द्र एडवोकेट- अपीलान्त
- 2- श्री महेशचन्द्र शर्मा एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक- 25.1.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट सं०- 1 व 2 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश T-40 सीपीसी के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख० नं० 0.42 हैक्टर, ख० नं० 899 रकबा 0.47 हैक्टर, ख० नं० 1195/1011 रकबा 0.25 हैक्टर वाके ग्राम चनाना है इस आराजी का पहले एक ही खसरा नं०

पीथा पुत्र सीता, कालु पुत्र हनुता, मामचन्द पुत्र माईधन थे । जिनका देहान्त हो गया । प्रार्थीगण कालूराम की औलाद है में से हैं । प्रार्थीगण उक्त आराजी में 1/3 हिस्से के खातेदार का तकार है । प्रतिवादीगण प्रार्थी/वादीगण के साथ आये दिन झगडा करते रहते है । विपक्षीगण के विरुद्ध दिनांक 20-5-1997 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आयन्दा आदेश तक भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करेंगे पाबन्द किया गया किन्तु विपक्षीगण आराजी मुतनाजा पर निमार्ण करने पर आमादा है । अतः रिहायशी हिस्से को छोडकर शेष आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई उक्त आराजी पर तहसीलदार चिडावा को रिसीवर नियुक्त कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति के बिन्दू को अलग अलग तय न कर आदेश पारित किया है जो खिलाफ कानून है । विवादित आराजी पर सरदाराराम, देवकरणा, रामदेव, सुरेन्द्र, मोहरसिंह, परसाराम मनरूप, महीपाल, केसराम, बनवारी, नेकीराम, दोदराम रामस्वरूप, जयराम, डेडाराम नाडराम आदि की विवादित आराजी पर रिहायशी गुवाडी बनी हुई है । जिस के बाबत अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है । जिसका रेस्पोंडेन्ट सं० 1 व 2 ने कोई खण्डन नहीं किया । बल्कि अपने प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट की रिहायशी गुवाडी बनी हुई स्वीकार की है । तथा रिहायशी जमीन को छोड कर रिसीवर नियुक्त करने की प्रार्थना की है । इसके बाद भी अदालत मातहत ने रिहायशी आराजी पर रिसीवर नियुक्त कर कानूनी भूल की है । रिहायशी गुवाडी के व्यक्ति दावं एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं है । जिनको बिना पक्षकार बनाये इस प्रकार का आदेश विधि के विपरित पारित किया है । इसके साथ ही तहसीलदार चिडावा को इस आराजी की किस्म परिवर्तन के आदेश दिये है जो गलत है । किसी भी जमीन की किस्म परिवर्तन बिना खातेदार की स्वीकृति के नहीं की जा सकती । खसरा नं० 224 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा का हैक्टर में 0000 रकबा

दर्ज किया है जो गत रकबे से 0.21 हैक्टर अधिक है यह अधिक रकबा ~~लेखा~~ कैसे हुआ तथा इसकी टीनेन्सी कैसे मिली स्पष्ट नहीं किया है। उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में करीब 0.10 हैक्टर जमीन पर उक्त व्यक्तियों की रिहायशी गुवाडिया बनी हुई है जो 20 साल पुरानी है। इस तथ्य का खण्डन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने नहीं किया तथा रेस्पोंडेन्ट ने यह दावा विवादित आराजी को पैत्रिक होना मानकर पेशा किया है किन्तु इन्होंने अपनी बहिन स्कमणी को पक्षकार तक नहीं बनाया जो आवश्यक पक्षकार थी। रेस्पोंडेन्ट ने विवादित आराजी को इन-मिडियों होना बताया है। इसके बाद भी अदालत मातहत ने बिना किसी उचित आधार के रिसीवर नियुक्त करने में कानूनी भूल की है। रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 व 2 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेधाना उनवानी सुल्तान बनाम सुरेशा मु०नं० 52/96 पेशा की किया जो दिनांक 29-9-97 को खारिज हो गया। तथा इसके बाद प्रार्थना पत्र 28/97 पेशा किया जिसमें अपीलान्ट ने मौका मुआयना करने का पेशा किया जिसका रेस्पोंडेन्ट ने कोई जबाब नहीं दिया। इसके बाद भी अदालत मातहत ने विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश विधि विरुद्ध पारित किया। ख०नं० 224 में से 10 दक्षिण की तरफ की। बीघा जमीन रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 व 2 के दादा कालूराम के हिस्से में आई जिसको रेस्पोंडेन्ट सं०-1 व 2 के पिता सोहनलाल ने बीरबल को बैयान कर दी। खसरा गिरदावरी सं०- 2009 से 2012 में 15 बिस्वा जमीन आबादी में दर्ज है। इसके बाद भी उक्त आराजी आबादी में दर्ज रही है। रेस्पोंडेन्ट का 1/3 हिस्सा भी माना जावे तो केवल 0.10 हैक्टर भूमि आती है जिसके लिये सम्पूर्ण आराजी को रिसीवर के कब्जे में दिये जाने के आदेश विधि के विपरित पारित किये हैं। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 व 2 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।


अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया

गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

बहुसंख्य विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान वकील रеспोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक बताते हुये कथन किया कि अदालत मातहत ने अपना निर्णय सभी तथ्यों पर गौर कर पारित किया है । अपीलान्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था इसके बावजूद भी विवादित आराजी पर लडाईं झगडा करते रहते रहे है अपीलान्ट के विद्वान वकील ने बहस में बताया कि जमाबन्दी से कोई टाई टल नहीं मिलता तो फिर कौनसे दस्तावेज से टाईटल मिलता है यह भी नहीं बताया । जमाबन्दी राजस्व रेकार्ड है जिसके आधार पर ही अधिकार मिलते हैं । जमाबन्दी में दर्ज सभी ~~पक्षधारणों~~ खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है । अदालत मातहत ने पक्षकारों पर और अधिक मुकदमें बाजी नहीं हो तथा आराजी की सुरक्षा हो इसके लिये अपना आदेश पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे

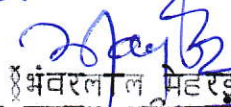
बहस बगौर समाप्त की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया । मिलल हकीयत 1998 में ख0नं0 224 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा के काश्तकार पीथा वन्द सीता, काजू पुत्र छाजूराम मामचन्द वन्द आईदान दर्ज है । सम्वत 2028 से 2031 में ख0नं0 224 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा पर धनरयणम पुत्र हरचन्द जाति महाजन, 1/3 हिस्सा, सोनिया वन्द काजू 0 1/3 हिस्सा झुथा पुत्र माईधन विधा हनुमान हि0 1/3 के नाम दर्ज है । जमाबन्दी सं0-2050 से 2053 में भी सोनिया वन्द काजू 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज है । झू-प्रबन्ध विभाग की खतौनी में ख0नं0 898, 899, 1195/1011 कुल किता-3 रकबा 1.14 हैक्टर में रस्पोडेन्ट का 1/3 हिस्सा सुलतान रामनिवास पि0 सोनिया के नाम दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया । गत खसरा नम्बर 224 के नये ख0नं0 898, 899, 1195/1011 बने हैं । नकल जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 में दर्ज खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है । विद्वान वकील अपीलान्ट ने इस बाबत नजीर पेश की है जो पूर्णतया साबित नहीं । यहाँ पर जमाबन्दी में दर्ज सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है । इसी क्रम में प्रस्तुत नजीर ~~सह~~खातेदारों को अस्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द नहीं किया जा सकता इसके तथ्य भिन्न है । विवादित आराजी इन-मिडियों होने पर अदालत मातहत

A handwritten signature in blue ink is present at the bottom left of the page. Below it is a circular stamp with text in Hindi, which is partially obscured and difficult to read.

ने अपना आदेश पारित किया है। जिसमें विवादित आराजी पर किसी प्रकार के विवाद न बडे। अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दुओं पर भी विवेचन किया है। जिसमें रेस्पोंडेन्ट के पक्ष में उक्त तीनों बिन्दुओं को साबित मानकर आदेश पारित किया है। हम भी ^{यही है} उचित मानते हैं कि पक्षकारों में और अधिक मुकदमे बाजी नहीं बडे तथा आराजी की भी सुरक्षा बनी रही। तथा पक्षकारों के हक अधिकार तो दावे में ~~उस~~ साक्ष्य सबूत के बाद निर्धारित होने है। विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरो के तथ्य भिन्न होने से प्रकरण पर चस्पा नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी हुन्हुनु का निर्णय दिनांक 10-10-1997 यथावत रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 25.1.2018 को सुनाया गया।


१ भंवरलाल मेहरडा २५/१/१८
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर